



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 4, 1995 (कार्तिक 13, 1917)
No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 4, 1995 (KARTIKA 13, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 915	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के द्वितीय प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)।	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1035	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	17	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निपटिका और महान्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायाधीश, वेल-विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1067
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1451	भाग III—खण्ड 2—वेस्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई वेस्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	881
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन प्रस्ताव द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	2365
भाग II—खण्ड 2—निष्पेक्ष तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्टें	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	155
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां प्रावि भी शामिल हैं)	*	भाग V—घरेलू और हिन्दी दोनों में और मूल्य के प्रावधानों को दर्शाने वाला अनुसूचक	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PAGE		PAGE
	PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	915
	PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	1035
	PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.	17
	PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.	1451
	PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.	*
	PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations.	*
	PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories).	*
	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence.	*
	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	1067
	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.	881
	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	—
	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.	2365
	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.	155
	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.	*

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्तूबर, 1995

संकल्प

सं० 9-4/92-सी० सी० [आई० ए०/जे० (भाग)]—
सरकार ने बाबा साहिब डॉ० बी० आर० अम्बेडकर की स्मृति में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार नामतः “सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार” (इसके पश्चात् “पुरस्कार” के रूप में माना जाएगा) शुरू करने का निर्णय लिया है।

2. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाएगा तथा इसमें 15 लाख रुपये और प्रशस्तिपत्र होगा। यह पुरस्कार व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा संगठन (संगठनों) को:—

--असमानता और अन्याय के विरुद्ध अनुकरणीय संघर्ष करने,

--शोषितों और सुविधावंचित लोगों की मांग का वृद्धतापूर्वक समर्थन करने,

--सामाजिक बदलाव के प्रति महत्वपूर्ण रूप से योगदान करने, तथा

--संघर्षरत सामाजिक समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक तालमेल और मानवीय प्रतिष्ठा के आदर्श की सेवा करने के लिए,

राष्ट्रीयता, जाति, धर्म या लिंगभेद का विचार न करते हुए दिया जाएगा।

3. पुरस्कार के व्यौरों को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तक यथासंभव व्यापक रूप से प्रचार किया जाएगा तथा उस वर्ष 30 नवम्बर तक प्राप्त हुए प्रस्तावों/सिफारिशों पर पुरस्कार ज्यूरी द्वारा विचार किया जाएगा।

4. पुरस्कार हेतु प्राप्त सिफारिशों की समीक्षा तथा पुरस्कार के लिए अंतिम चयन भारत के उपराष्ट्रपति की

अध्यक्षता में भारतीय नागरिकों की सात सदस्यों की उच्चस्तर ज्यूरी द्वारा किया जाएगा।

5. पुरस्कार की योजना के लिए वित्त सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

6. कल्याण मंत्रालय अथवा इसकी एजेंसी पुरस्कार योजना को कार्यान्वित करेगी।

7. पुरस्कार की योजना का व्यौरा तथा इसका प्रशासन इसके साथ संलग्न प्रक्रिया संहिता में दिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों तथा भारत सरकार के सभी सचिवों को सूचना के लिए भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गंगा दास
संयुक्त सचिव

सामाजिक परिवर्तन के लिए

डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रक्रिया संहिता

अध्याय—1

पुरस्कार का वर्णन

यह पुरस्कार “डॉ० अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार” के नाम से जाना जाएगा। इसकी स्थापना भारत तथा पूरे मानव परिवार के प्रति डॉ० भीमराव रामजी अम्बेडकर

द्वारा समर्पित उल्लेखनीय सेवाओं की याद बनाए रखने के लिए की गई है।

अध्याय—4

पुरस्कार की अवधि

यह व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा संगठन (संगठनों) को—

- प्रसन्नता और अन्याय के विरुद्ध अनुकरणीय लड़ाई लड़ने,
- शोषितों और सुविधा वंचित लोगों की मांग का दृढ़तापूर्वक समर्थन करने,
- सामाजिक बदलाव के प्रति महत्वपूर्ण रूप में योगदान करने,
- संवर्धित सामाजिक समूहों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा सामाजिक तालमेल और माधवीय प्रतिष्ठा के भावार्थ की सेवा करने के लिए प्रदान किया जाएगा।

1. यह पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाएगा। तथापि, यदि कोई भी प्रस्ताव योग्य नहीं पाया जाता है तो ज्युरी उस वर्ष के लिए पुरस्कार स्वयं गत करने के लिए स्वतंत्र होगी।
2. केवल हाल की (नई) कृतियों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि प्रारम्भिक कृतियों पर भी विचार किया जा सकता है यदि इनकी महत्ता स्थायी प्रकृति की हो।

अध्याय—5

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की क्षमता

अध्याय—2

पुरस्कार का मूल्य

1. प्रत्येक वर्ष एक पुरस्कार होगा। इसमें 1.5 मिलियन की धनराशि होगी जिसका भुगतान पुरस्कारप्राप्तकर्ता की मनोवांछित मुद्रा में किया जाएगा। इसके साथ एक प्रशस्ति-पत्र भी होगा।
2. संयुक्त पुरस्कार :—यह पुरस्कार किसी निर्धारित वर्ष में ज्युरी द्वारा उपयुक्त पाए गए एकाधिक व्यक्तियों को संयुक्त रूप में दिया जा सकता है।
3. मरणोपरान्त पुरस्कार :—सामान्यतः यह पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिया जाएगा। तथापि यदि इस संहिता में निर्धारित रीति के अनुसार ज्युरी को प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद मृत्यु होती है तो यह पुरस्कार मरणोपरान्त दिया जा सकता है।

अध्याय—3

पुरस्कार के लिए पात्रता

1. राष्ट्रियता, जाति, बंश-अथवा लिंग का विचार किए बिना कोई भी पुरस्कार के लिए पात्र होगा।
2. आपवाक्कित मामलों में इस पुरस्कार के लिए कोई संगठन भी पात्र हो सकता है, बशर्ते कि संश्लिष्ट क्षेत्र में उसने कोई विशिष्ट कार्य किया हो अथवा उसके विशिष्ट योगदान का रिकार्ड रहा हो।
3. पुरस्कार के लिए ज्युरी द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों/संगठनों पर विचार किया जाएगा जिनकी सिफारिश इस संहिता के अध्याय 5 में वर्णित मानदंडों के अतुल्य विशिष्ट रूप में की गई हो।
4. ज्युरी द्वारा किसी भी व्यक्तिगत आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कार के लिए प्रस्तावों पर सिफारिश करने की क्षमता निम्नलिखित को प्राप्त होगी :—

- (क) ज्युरी के भूतपूर्व सदस्य,
- (ख) वे व्यक्ति जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त किए हों,
- (ग) भारतीय संसद सदस्य,
- (घ) अन्य देशों की राष्ट्रीय विधायिकाओं के अध्यक्ष/पीठासीन अधिकारीगण।
- (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता संघ,
- (च) विश्वविद्यालयों के अध्यक्षगण और उप कुलपति, राजनीति विज्ञान, इतिहास, विधि, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान के प्रोफेसरगण,
- (छ) विदेश स्थित भारतीय मिशनो के अध्यक्ष,
- (ज) कोई और व्यक्ति जिसे ज्युरी पुरस्कार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने को आमंत्रित करे।

2. पुरस्कार के व्योरे जहां तक सम्भव हों, प्रत्येक वर्ष की प्रथम जुलाई तक प्रकाशित कर दिए जाएंगे।

3. पुरस्कार के लिए ज्युरी द्वारा उन प्रस्तावों/सिफारिशों पर विचार किया जाएगा जो पुरस्कार दिए जाने वाले वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में 30 नवम्बर तक प्राप्त हुए हों।

4. विचार किए जाने वाले प्रस्ताव/सिफारिशों के पीछे समुचित औचित्य चाहिए।

अध्याय—6

पुरस्कार प्राप्तकर्ता का चयन

1. सिफारिशों की जांच तथा पुरस्कार के लिए अन्तिम रूप से चयन एक ज्यूरी द्वारा किया जाएगा जिसकी नियुक्ति इस उद्देश्य के लिए भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
2. ज्यूरी में सात सदस्य होंगे जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय होगी।
3. उप-राष्ट्रपति तथा लोक सभाध्यक्ष इस ज्यूरी के स्थायी तथा पदेन सदस्य होंगे। उप-राष्ट्रपति इस ज्यूरी के अध्यक्ष होंगे। यदि कुछ कारणवश उनके लिए उपस्थित हो पाना सम्भव न हो तो लोक सभाध्यक्ष, अध्यक्ष की हसियत से कार्य करेंगे।
4. ज्यूरी के अन्य पांच सदस्यों का मनोनयन भारत के उप-राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:—
 - (1) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष।
 - (2) एक उम्रति प्राप्त शिक्षाविद्।
 - (3) एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिसने कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशिष्ट कार्य किया हो।
 - (4) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अनुभव रखने वाले एक व्यक्ति सहित भारतीय सार्वजनिक जीवन के दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति।
5. ज्यूरी के सदस्यगण तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तीन वर्ष बाद दो स्थायी पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तथापि वे पुनर्नियुक्त के लिए पात्र होंगे।
6. कार्यवधि के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में शेष अवधि के लिए दूसरे सदस्य की नियुक्ति की जाएगी।
7. ज्यूरी की बैठक के लिए कोरम तब पूरा होगा जब कम से कम चार सदस्य उपस्थित हों।
8. ज्यूरी का निर्णय खुले मतदान की विधि से बहुमत द्वारा होगा। बराबरी की स्थिति में बैठक के अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।
9. पुरस्कार के संबंध में ज्यूरी के विचार-विमर्श, मत एवं कार्यवाही न तो सार्वजनिक किए जाएंगे और न ही अन्यथा प्रकाशित किए जाएंगे।
10. जहां तक सम्भव हो ज्यूरी अपना निर्णय प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी तक सुनएगी।
11. ज्यूरी का निर्णय अन्तिम होगा और उसके विरुद्ध कोई अपील अथवा विरोध नहीं किया जा सकता।

अध्याय—7

पुरस्कार प्रदान किया जाना

1. यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा।
2. पुरस्कार प्राप्तकर्ता को पुरस्कार लेने के लिए स्वयं उपस्थित होने तथा जिस कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है उसके संबंध में एक सार्वजनिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
3. कल्याण मंत्रालय के अधीन डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान इस पुरस्कार का संचालन करेगा और पुरस्कार प्राप्तकर्ता के अनुरोध के अनुरूप समय और स्थान पर पुरस्कार की राशि का भुगतान करेगा।
4. यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय न हो तो पुरस्कार की धनराशि का भुगतान विद्यमान विनियम दरों पर पुरस्कार प्राप्तकर्ता की पसंदीदा मुद्रा में किया जाएगा।
5. यदि कोई पुरस्कार लेने वाला पुरस्कार लेना अस्वीकार करे तो पुरस्कार की राशि भारत सरकार को शीघ्र लौटा दी जाएगी लेकिन यदि पुरस्कार लेने वाला इसे स्वीकार तो करता हो किन्तु छत्तीस महीनों की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं कर पाता हो तो भी पुरस्कार की राशि भारत सरकार के पास लौटा दी जाएगी।

अध्याय—8

सामान्य

1. ज्यूरी अपनी कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके इस संहिता में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है। यदि प्रस्तावित संशोधन को भारत सरकार का अनुमोदन मिल जाता है तो यह भारत सरकार द्वारा निश्चित तारीख से लागू हो जाएगा।
2. भारत सरकार भी ज्यूरी के साथ पहले परामर्श करके इस संहिता में संशोधन ला सकती है।
3. इस पुरस्कार का संचालन कल्याण मंत्रालय के डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान द्वारा किया जाएगा और उसके लिए सम्पूर्ण व्यय की राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
4. इस पुरस्कार के लिए सचिवालय डॉ० अम्बेडकर प्रतिष्ठान और कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

नई दिल्ली दिनांक, 11 अक्टूबर 1995

संकल्प

सं० ई० 11011/20/92—हिन्दी : नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय (नागर विमानन विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में 9 मार्च 1995 के समसंख्यक संकल्प में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :-

संकल्प के पैरा 1 में क्रम संख्या 1—नागर विमानन और पर्यटन मंत्री—अध्यक्ष के नीचे क्रम संख्या 2 के रूप में नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री को उपाध्यक्ष के

रूप में शामिल किया जाए और उससे आगे की क्रम संख्याओं को तदनुसार पढ़ा जाये।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रघुनाथ सहाय,
निदेशक (राजभाषा)

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi, the 10th October 1995

RESOLUTION

No. 9-4/92-CC(IA)/1(Pt).—Whereas Government have decided to institute an International Award in the memory of Baba Saheb Dr. B. R. Ambedkar known as "Dr. Ambedkar International Award For Social Change" (hereinafter referred to as the Award).

2. The Award will be given annually and will carry an amount of Rs. 1.5 million and a citation. It shall be conferred on individual(s) or organisation(s), regardless of nationality, race, creed or sex :

- for waging an exemplary fight against inequality and injustice;
- for resolutely espousing the cause of the exploited and underprivileged;
- for contributing significantly to social change; and
- for bringing about reconciliation among conflicting social groups and serving the ideal of social harmony and human dignity.

3. Details of the Award shall be disseminated as widely as possible by 1st July every year, and proposals/recommendations received upto 30th November of the same year shall be considered by the Jury for the Award.

4. The scrutiny of the recommendations and final selection for the Award shall be made by a high level Jury of seven members of Indian nationals, under the Chairmanship of Vice President of India.

5. The finances for the scheme of Award shall be provided by the Government.

6. The Ministry of Welfare or its agency will administer the Award.

7. The details of the scheme of the Award and its administration are given in the Code of Procedure attached herewith.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all Chief Secretaries of all States/Union Territories and Secretaries to the Government of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GANGA DAS,
Joint Secy.

CODE OF PROCEDURE

DR. AMBEDKAR INTERNATIONAL AWARD FOR SOCIAL CHANGE

CHAPTER I

DESCRIPTION OF THE AWARD

The Award shall be known as "Dr Ambedkar International Award". The award has been instituted to commemorate the signal services rendered by Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar to India and the human family at large. It shall be conferred upon the individual(s) or organisation(s) :-

- for waging an exemplary fight against inequality and injustice;
- for resolutely espousing the cause of the exploited and underprivileged;
- for contributing significantly to social change;
- for bringing about reconciliation among conflicting social groups and serving the ideal of social harmony and human dignity;

CHAPTER II

VALUE OF THE AWARD

1. There shall be one Award each year. It shall carry an amount of Rs 1.5 million which will be paid in the preferred currency of the recipient. It shall also carry a citation.
2. JOINT AWARD : The Award may be presented jointly to more than one person, who may be considered by the Jury to be equally deserving of recognition in a given year.
3. POSTHUMOUS AWARD : Normally the Award will not be presented posthumously. If, however, the death occurred subsequent to a proposal having been submitted to the Jury in the manner stipulated in this Code, then the Award may be presented posthumously.

CHAPTER III

ELIGIBILITY FOR THE AWARD

1. All persons, regardless of nationality, race, creed or sex, shall be eligible for the Award.
2. An organisation may also be eligible for the Award, in exceptional cases, having substantial outstanding work or track record of outstanding contributions in the relevant field.

3. Only persons/organisations recommended in writing in accordance with the criteria laid down in Chapter V of this Code will be considered by the Jury for the Award.
4. No personal applications shall be entertained by the Jury.

CHAPTER IV

PERIOD OF THE AWARD

1. The Award shall be conferred annually. However, if none of the proposals merit recognition, the Jury will be free to withhold the Award for that year.
2. Only recent work(s) shall be considered. However, the earlier work(s) may also be considered if its significance has been of an abiding nature.

CHAPTER V

COMPETENCE TO SUBMIT PROPOSALS

1. Competence to recommend the proposals for the Award shall be enjoyed by :
 - (a) Former Members of the Jury;
 - (b) Persons who have received the Award;
 - (c) Members of Parliament of India;
 - (d) Speaker/Presiding Officers of National Legislatures of other countries;
 - (e) The Bar Associations of Supreme Court of India and High Court of each State/U.T.;
 - (f) Presidents and Vice-Chancellors of Universities, professors of Political Science, History, Law, Economics, Sociology, Philosophy and Natural Sciences;
 - (g) Heads of Indian Missions abroad;
 - (h) Any other person whom the Jury may wish to invite to submit proposals for the Award.
2. Details of the Award shall be disseminated as widely as possible by 1st July, every year.
3. Proposals/recommendations received upto 30th November of the year preceding the year in which the Award is to be given shall be considered by the Jury for the Award. The Chairperson of the Jury may, however, extend the time for submission of recommendations in general or with reference to a particular proposal.
4. Proposals/recommendations to be considered should be supported by adequate jurisdiction.

CHAPTER VI

SELECTION OF AWARDEE

1. The scrutiny of the recommendations and final selection for the Award shall be made by a Jury to be appointed for this purpose by the Vice-President of India.
2. The Jury shall consist of seven Members all of whom shall be Indian nationals.
3. The Vice-President and the Speaker-Lok Sabha, shall be permanent ex-officio Members of the Jury. The Vice-President shall be the Chairperson of the Jury. If for some reason it is not possible for him to be present then the Speaker shall act as the Chairperson.
4. The other five Members of the Jury shall be nominated by the Vice-President of India in the following manner :
 - (i) Chairperson of the National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.
 - (ii) One eminent educationist.

(iii) One eminent social worker who has done outstanding work for the uplift of weaker sections.

(iv) Two eminent persons from public life in India including one with experience of international affairs.

5. Members of the Jury shall be appointed for a period of three years. After three years members other than the two permanent ex-officio Members shall retire. They shall, however, be eligible for reappointment.

6. In case of the death of a Member during the tenure another shall be appointed in his place for the unexpired part of that term.

7. Presence of at least four Members will constitute the quorum for the meeting of the Jury.

8. The decision of the Jury shall be by a majority of vote caste by open ballot. In the event of tie, the Chairperson of the meeting shall have a casting vote.

9. The discussions, deliberations, opinions and proceedings of the Jury in connection with the Award shall not be made public or otherwise revealed.

10. The Jury shall announce its decision as far as possible by 15th February, every year.

11. Decision of the Jury shall be final and no appeal or protest could be made against them.

CHAPTER VII

PRESENTATION OF THE AWARD

1. The Award will be presented at a special ceremony at New Delhi on 14th April every year.
2. The awardee shall be invited to receive the Award in person and also to give a public lecture connected with the work recognised for the Award.
3. Dr. Ambedkar Foundation, under the Ministry of Welfare, will administer the Award and will make payment of the Award money at the time and place requested by the awardee.
4. If the awardee is not an Indian the Award money shall be paid in the preferred currency of the recipient at the prevailing exchange rates.
5. If an awardee declines the Award, the Award money will immediately revert to the Government of India but if the awardee accepts yet fails to draw the Award money within a period of thirty six months then also the Award money shall revert to the Government of India.

CHAPTER VIII

GENERAL

1. The Jury may propose an amendment in the Code by passing a Resolution by 2/3rd majority of the total membership of the Jury. In case the proposed amendment is approved by the Government of India, it shall come into force from the date decided by the Government of India.
2. The Government of India may also make a amendment in the Code with prior consultation with the Jury.
3. The Award will be administered by Dr. Ambedkar Foundation, under the Ministry of Welfare, for that all the expenses incidental thereto shall be provided by the Government of India.
4. The Secretariat for the Award shall be provided by Dr. Ambedkar Foundation and Ministry of Welfare.

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM
(DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION)

New Delhi, the 11th October 1995

RESOLUTION

No. E. 11011/20/92-Hindi.—The following amendments are hereby made in the Resolution of even number dated 9th March, 1995 regarding constitution of Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Civil Aviation & Tourism (Department of Civil Aviation) :

In para 1 of the Resolution, below Sl. No. 1—Minister of Civil Aviation and Tourism—Chairman, the name of Minister of State in the Department of Civil Aviation be included at Sl. No. 2 and the subsequent Sl. Nos. may be read accordingly.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administration, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

RAGHUNATH SAHAI,
Director (O.L.)